

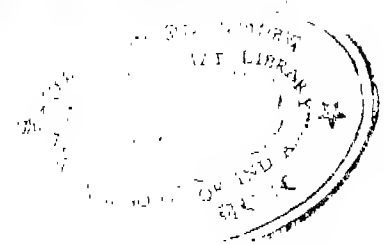


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 11]
No. 11]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 1990/चैत्र 15, 1912
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 1990/CHAITRA 15, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स
(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1990

सं. 3910 :— बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में और आगे संशोधन करने के लिए एनद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) ये विनियम ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1990 कहे जायेंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. विनियम 3 में संशोधन — परिभाषाएं :

- 3(ब) "वेतन" का अर्थ पक्षोन्नति अवरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन है।

3(म) : "तनखाह" से मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का योग अभिप्रेत है।

विनियम 1 में संशोधन — ग्रेड और वेतनमान

4(1) : दिनांक 1-2-1984 को और इस तारीख से अधिकारियों के चार निम्नलिखित ग्रेड होंगे जिनके वेतनमान प्रत्येक ग्रेड के नामने लिखे अनुसार होंगे :—

(क) सर्वोच्च कार्यपालक ग्रेड :

वेतनमान — VII रुपये 4100 — 125 — 4600

वेतनमान — VI रुपये 3850 — 125 — 4350

(ख) वरिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड :

वेतनमान — V रुपये 3575 110-3685-115-3800

वेतनमान — IV रुपये 2925 — 105 — 3450

(ग) मध्यम प्रबन्ध ग्रेड :

वेतनमान — III रुपये 2650 — 100 — 3250

वेतनमान — II रुपये 1825 — 100 — 2925

(घ) कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड :

वेतनमान — I रुपये 1175-60-1475-70-

1895 ई. बी. 95-2275-

100-2675

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से से प्रत्येक ग्रेड के लिए विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:—

(क) सर्वोच्च कार्यपालक ग्रेड :

वेतनमान-VII रुपए 6100-150-7000

वेतनमान-VI रुपए 5950-150-6550

(ख) वरिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड :

वेतनमान-V रुपए 5350-150-5950

वेतनमान-IV रुपए 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ग) मध्यम प्रबन्ध ग्रेड :

वेतनमान-III रुपए 4020-120-4260-130-4910

वेतनमान-II रुपए 3060-120-1260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड :

वेतनमान-I रुपए 2100-120-4020

वर्तमान सरकार के विनियम 8 के तहत जारी किए गए, मार्गनिर्देशों के अनुसार उक्त वेतन में फिट किए गए प्रत्येक अधिकारी को, जो नियत विधि को लागू वेतनमान द्वारा शामिल हो, सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार उक्त वेतन निर्धारित वेतनमान में फिट किया जाएगा।

विनियम 5 में संशोधन—वेतनवृद्धियां

5(1) :

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उप खंडों के अधधीन मंजूर की जाएंगी:—

(क) विनियम 4(1) में उल्लिखित विभिन्न वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतनवृद्धियां सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी किए जाने पर, वार्षिक आधार पर होंगी और जिस महीने में वे देय होंगी, उसके पहले दिन प्रदान की जाएंगी।

(ख) वेतनमान - I और वेतनमान - II में कार्यरत अधिकारियों को उनके संबंधित वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष बाद, नीचे (ग) में बताए अनुसार ही अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति अवरोध वेतनवृद्धि (या) सहित आगे वेतनवृद्धि उनके द्वारा दक्षता रोध पार किए जाने पर मंजूर की जाएंगी।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित ऐसे अधिकारी, जो मध्यम प्रबन्ध ग्रेड वेतनमान-II और III की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हों, वेतनमान-II और III, यथास्थिति, के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष पूरे करने के बाद पदोन्नति अवरोध वेतनवृद्धि (या) प्राप्त करेंगे परन्तु ये वेतनवृद्धियां वेतनमान - II के अंतिम चरण में अधिकारियों के लिए 130 रुपये की अधिकतम दो और वेतनमान -III के

अंतिम चरण में अधिकारियों के लिए 140 रुपये की अधिकतम एक होंगी।

टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियां की मंजूरी पदोन्नति के बराबर नहीं होगी। ऐसी वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के बाद भी अधिकारी अपने मूल वेतनमान-I अथवा वेतनमान-II, यथास्थिति, के विशेषाधिकार, परिणतिवृद्धियां, इत्यादी उत्तमदायित्व अथवा पद प्राप्त करते रहेंगे।

5(2) :

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से ऐसे अधिकारियों को, जो वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच रहे हों अथवा पहुंच चुके हों, तथा पदोन्नति के अभाव किसी अन्य प्रकार से आगे न बढ़ सकने हों, उन्हें सरकारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अधीन सी ए आई आई आई बी परीक्षा पास करने पर अनिवार्य वेतनवृद्धियों के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता भत्ता निम्नानुसार दिया जायेगा:—

सीएआईआईबी का केवल : एक वर्ष के बाद 100 भाग I पास करने वाले रु. प्रति माह जिसमें से 75 रु. अधिवार्षिकी लाभों के लिए होंगे।

सीएआईआईबी के दोनों : (i) एक वर्ष के बाद 100 भाग I पास करने वाले रु. प्रति माह जिसमें से 75/- रु. अधिवार्षिकी लाभों के लिए होंगे।

(ii) दो वर्ष के बाद 250 रु. प्रति माह जिसमें से 200 रु. अधिवार्षिकी लाभों के लिए होंगे।

टिप्पणी :

यदि ऐसा अधिकारी, जो व्यावसायिक योग्यता भत्ता ले रहा है, अगले उच्चतर स्केल में पदोन्नत हो जाए, तो उसे ऐसे उच्चतर स्केल में फिट किए जाने पर सीएआईआईबी उतीर्ण करने के लिए अनिवार्य वेतनवृद्धि (या) उस स्केल में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक दी जाएगी और यदि उस स्केल में कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध न हो या केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध हो तो वह अधिकारी वेतनवृद्धि (या) के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता भत्ता पाने का हकदार होगा।

विनियम 21 में संशोधन—मंहगाई भत्ता

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से मंहगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी:—

(i) मंहगाई भत्ता, अखिल भारतीय औसत श्रमजीवी वर्ग उन्मुख ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960= 100 की तिमाही औसत में 600 प्वाइंट के ऊपर प्रत्येक 4 प्वाइंट के बढ़ने या घटने पर देय होगा।

(ii) मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार देय होगा:

(i) 1650 रु. तक 'वेतन' का 0.67% जमा,

(ii) 1650 रु. से अधिक 2835 रु. तक 'वेतन' का 0.55% जमा,

(III) 2835 रु. से अधिक 4020 रु. तक 'वेतन' का 0.33 जमा,

(IV) 4020 रु. से अधिक 'वेतन' का 0.17%

विनियम 22 में संशोधन - मकान किराया भत्ता

22(1) : दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवास मुहैया करवाया जाए, तो उससे वेतनमान के, जिसमें उसे फिट किया जाए, प्रथम चरण के वेतन का 6% अथवा आवास का मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जायेगा।

22(2) : दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से, जहाँ अधिकारी को बैंक द्वारा आवास मुहैया न करवाया गया हो, वहाँ वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा :—

जहाँ कार्यस्थल इनमें से कहीं हो देय मकान किराया भत्ता

- (i) सरकार के मार्गनिर्देशों के 'वेतन' का 14% परन्तु अनुधार समय-समय पर अधिकतम 375/- यथाविनिर्दिष्ट 'क' श्रेणी के प्रमुख शहर और समूह 'क' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र
- (ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान और वेतन का 12% परन्तु समूह 'ख' में परि- अधिकतम 300/- रुपये योजना क्षेत्र केन्द्र
- (iii) क्षेत्र II और राज्य राज- 'वेतन' का 10% परन्तु धानियां तथा ऊपर I अधिकतम 250/- रु. और II में सम्मिलित न की गई संघ राज्य प्रदेशों को राजधानियां
- (iv) क्षेत्र -III 'वेतन' का 8% परन्तु अधिकतम 225/- रुपये

परन्तु, यदि अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करे तो उसे जिस वेतनमान में रखा गया है उसके प्रथम चरण के वेतन के 6% से अधिक, उसके द्वारा आवास के लिए वस्तुतः प्रदत्त किराया देय होगा जो अन्यथा देय अधिकतम मकान किराए भत्ते के 160% तक होगा।

22(3) : यदि अधिकारी अपने मकान में रहता है तो वह उप विनियम (2) के परन्तुक में यथाउल्लिखित आधार पर मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा मानो वह नीचे 'क' अथवा 'ख' में से अधिक वाले के बराबर हिस्से के बराबर रकम मासिक किराए के रूप में अदा कर रहा हो :—
इनका पूर्ण योग :—

क

(I) उस मकान के लिए दिए जाने वाले पालिका कर, और

(II) भूमि के मूल्य सहित मकान की पूंजीगत लागत का 12% और यदि वह मकान किसी भवन का एक हिस्सा हो तो उस मकान के लिए लगने वाली भूमि की पूंजीगत लागत

का सगानुपाती अंश, विशेष जुड़नारों जैसे एयरकंडीशनर की लागत को छोड़कर, या

ख

मकान के पालिका मूल्य निर्धारण के लिए लगाया गया वार्षिक किराया मूल्य

स्पष्टीकरण :

(1) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "मानक किराए" का अर्थ है :—

(क) जिस मकान का स्वामी बैंक है, उसके मामले में वह मकान किराया, जो सरकार में प्रचलित हिसाब लगाने की प्रक्रिया के अनुसार बनता हो।

(ख) यदि मकान बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो तो बैंक द्वारा देय संवेदात्मक किराया।

विनियम 23 में संशोधन—नगर प्रतिकार भत्ता

23(I) : दिनांक 1-11-87 को और इस तारीख से यदि वह नीचे सारणी के कालम 1 में दिए गए स्थान पर कार्यरत है, तो उस स्थान के सामने कालम 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकार भत्ता बशर्ते कि पण्जी और मारमुगाओ के शहरी समूह में भिन्न गोआ राज्य के स्थलों पर नगर प्रतिकार भत्ता, जहाँ यह दिनांक 1-11-1987 को देय नहीं था, दिनांक 20-8-1988 से देय होगा।

स्थान	दरें
1	2
(क) क्षेत्र 1 और गोआ राज्य में विभिन्न स्थान	मूल वेतन का 6-1/2% परन्तु अधिकतम 220 रुपये प्रति माह
(ख) ऊपर 'क' में शामिल न किए गए 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों तथा राज्य राजधानियां एवं चण्डीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर	मूल वेतन का 4% परन्तु अधिकतम 135/- रुपये प्रति माह

23 (V) प्रतिनियुक्ति भत्ता

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां ग्रहण करने का विकल्प दे सकता है जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया हो। दूसरे विकल्प के रूप में वह अपने वेतन के साथ-साथ वेतन के 12% और अधिकतम 700/- रुपये का प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे तब मिलते जब वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात किया गया होता।

परन्तु यदि उस ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्ति किया जाए जो उसी स्थान पर स्थित है, जहाँ प्रतिनियुक्ति से पौरन

पहले वह तैनात था तो उसे उसके वेतन के 6% के बराबर और अधिकतम 350 रुपये प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

परन्तु यदि अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में अथवा बैंकिंग सेवा भती बोर्ड में प्रतिनियुक्त किया जाए तो वह मूल वेतन का 6% और अधिकतम 350 रुपये प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का हकदार होगा।

23(VI) स्थानापन्न भत्ता :

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से, यदि उसे एक बार कम से कम 7 दिन की निरन्तर अवधि के लिए या किन्हीं एक कलेंडर माह में कुल 7 दिन किसी उच्चतर ग्रेड के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करवाया जाए तो उसे उस अवधि के लिए जिसमें उसने स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, उसके वेतन के 6 प्रतिशत के बराबर परन्तु अधिकतम 250 रुपये प्रति माह स्थानापन्न भत्ता मिलेगा। स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए वेतन माना जायेगा परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं परन्तु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अन्तर्गत एक मात्र पदों के वर्गीकरण के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी उच्चतर ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए आता है तो जिस तारीख को वर्गीकरण का पुनरीक्षण किया जायेगा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि तक वह स्थानापन्न भत्ता पाने का पात्र नहीं होगा।

23 (VII) लेखा समापन भत्ता :

वित्तीय वर्ष 1989-90 की ओर से, यदि वह ऐसी शाखा में तैनात है जहां बहिषों को 31 मार्च और 30 सितम्बर को बन्द किया जाता है, वहां प्रत्येक लेखा समापन के लिए 150 रु० का समापन भत्ता।

23(X) पहाड़ और ईंधन भत्ता :

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से, यदि वह नीचे सारणी के कालम 1 में उल्लिखित स्थान पर कार्य कर रहा है तो इस सारणी के कालम 2 में उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता :—

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा टाऊन	वेतन का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 130 रु. प्रति माह
(ii) 1500 मीटर और अधिक परन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 6-1/2 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 160 रुपये प्रति माह
(iii) 3000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 15 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 600 रु. प्रति माह

टिप्पणी:—

(क) ऐसे स्थानों पर, जो 750 मीटर से अधिक ऊंचाई पर न हों और जिनके आसपास अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ हों जिन पर 1000 मीटर या अधिक की ऊंचाई को पार किए बिना पहुंचना संभव न हों, तैनात अधिकारियों को उसी दर से पहाड़ और ईंधन भत्ता दिया जायेगा जो 1000 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों पर देय है।

(ख) किसी ऐसे केन्द्र पर, वर्तमान में दिया गया पहाड़ और ईंधन भत्ता समाप्त कर दिया गया समझा जाएगा जो ऊपर दिए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। दिनांक 1-11-1987 और दिनांक 30-4-89 की अवधि में पहले ही दिया जा चुका उक्त भत्ते की बमूली नहीं की जायेगी। 1 मई 1989 से, इस तारीख को या उससे पहले एक केन्द्र पर तैनात अधिकारियों के मामले में, उनके उसी केन्द्र पर एक ही वेतनमान में तैनात रहने की तारीख तक पुराने प्रावधानों के ही तहत 30 अप्रैल की स्थिति के अनुसार उन्हें प्रदत्त भत्ते की मात्रा को सुरक्षित रखा जायेगा।

विनियम 24 में संशोधन—चिकित्सा सहायता और अस्प-तालीकरण व्यय :—

24(1) एक अधिकारी अपने लिए और अपने परिवार के लिए वास्तव में किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का निम्नलिखित आधार पर पात्र होगा अर्थात् :—

(क) चिकित्सा व्यय

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से, नीचे दी गई सारणी के कालम 1 में निर्दिष्ट वेतन सीमा में किसी अधिकारी के तथा उसके परिवार के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति एक प्रमाणपत्र के आधार पर की जा सकती है जो व्यय किए जाने के बारे में उक्त अधिकारी द्वारा दावे की रकम की लेखा विवरणी सहित दिया जायेगा। उसकी सीमा सारणी के कालम 2 में बताएं अनुसार होगी :—

सारणी	
वेतन सीमा	प्रतिपूर्ति सीमा प्रति वर्ष
1	2
2100 रुपये से 3060 रुपये प्रति माह	600 रुपये
3061 रुपये प्रतिमाह और अधिक	800 रुपये

टिप्पणी :

किसी अधिकारी को अप्राप्त चिकित्सा सहायता इतनी सूचित करने दी जायेगी कि वह किसी भी समय ऊपर उपबधित रकम के 3 गुणा से अधिक न बढ़े।

स्पष्टीकरण :—

इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी के "परिवार" में पत्नी/पति, पूर्णतया आश्रित बच्चे और पूर्णतया आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

(ख) अस्पताल के इलाज पर खर्च

(i) दिनांक 1-4-1989 को और इस तारीख से जिन रोगों के लिए अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना पड़े, उन सभी मामलों में अस्पताल के इलाज पर खर्चों की स्वयं अधिकारी के लिए 90 प्रतिशत और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 60 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(v) दिनांक 1-4-1989 को और इस तारीख से ऐसे निम्नलिखित रोगों के सम्बन्ध में जिनके लिए घर पर रह कर इलाज करवाना आवश्यक हो, जिस मान्यताप्राप्त अस्पताल प्राधिकारियों व बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, किए गए चिकित्सा व्यय को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने पर किया गया खर्च माना जायेगा और एक अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक और उसके परिवार के सदस्य के मामले में 60% तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी :—

कैंसर, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय रोग, ट्यूमर, चेचक, चूरेसी, डिफ्थीरिया, कुष्ठ रोग, गुर्दा रोग।

विनियम 25 में संशोधन—आवासीय सुविधा :

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से, कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध करवाए जाने के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं होगा। फिर भी, बैंक चाहे तो अधिकारी द्वारा अपने वेतनमान के, जिसमें उसे फिट किया गया हो, पहले चरण के वेतनमान का 6 प्रतिशत या आवास का मानक किराया, जो भी कम हो, अदा करने पर आवास मुहैया कर सकता है परन्तु, यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी दिया जाए तो उस अधिकारी से बैंक द्वारा उसके वेतनमान के प्रथम चरण के वेतन के $1\frac{1}{2}$ के बराबर रकम भी वसूल की जायेगी परन्तु शर्त यह है कि जहां बैंक इस प्रकार से आवास मुहैया करता है, वहां पानी, बिजली, गैस, सफाई का खर्च अधिकारी को वहन करना होगा।

विनियम 34 में संशोधन—बीमारी की छुट्टी :—

34(1) दिनांक 1-1-1989 को और इस तारीख से कोई अधिकारी सेवा के पूरे किए प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की बीमारी की छुट्टी लेने का पात्र होगा परन्तु, यह छुट्टी पूरी सेवा के दौरान अधिक से अधिक 18 महीने की होगी ऐसी छुट्टी पूरी सेवा के दौरान 540 दिन तक संचित हो सकती है और बैंक को स्वीकार्य

या बैंक के स्वनिर्णय पर, उसके ही खर्च पर, उसके द्वारा मनोनीत किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश करने पर ही ली जा सकती है।

विनियम 35 में संशोधन—अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी :

दिनांक 1-1-1989 को और इस तारीख से, जहां अधिकारी ने 24 वर्ष की सेवा कर ली हो तो वह 24 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए, एक माह की दर से अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी लेने का हकदार होगा परन्तु, कि यह अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी अधिक से अधिक 3 माह होगी।

विनियम 41 में संशोधन—यात्रा का वाहन और यात्रा पर व्यय :

दिनांक 1-4-1990 को और इस तारीख से, जब कभी किसी अधिकारी को छुट्टी पर यात्रा करने की आवश्यकता पड़े तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :—

(i) कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड का अधिकारी रेलगाड़ी से प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित स्लीपर में यात्रा कर सकता है। तथापि, वह विमान (किफायती श्रेणी) से भी यात्रा कर सकता है यदि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबार की आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करने की मंजूरी दी जाए।

(ii) मध्यम प्रबन्ध ग्रेड का अधिकारी रेल गाड़ी में प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित स्लीपर में यात्रा कर सकता है। तथापि वह विमान (किफायती श्रेणी) से भी यात्रा कर सकता है। तथापि, वह विमान (किफायती श्रेणी) से भी यात्रा कर सकता है यदि तय की जाने वाली दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो परन्तु, वह कम दूरी के लिए भी विमान (किफायती श्रेणी) से यात्रा कर सकता है यदि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबार की आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

(iii) वरिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड अथवा सर्वोच्च कार्यपालक ग्रेड के अधिकारी रेलगाड़ी में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा विमान (किफायती श्रेणी) में यात्रा कर सकते हैं।

(iv) वरिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड अथवा सर्वोच्च कार्यपालक ग्रेड के अधिकारी, उन स्थानों के बीच कार द्वारा यात्रा कर सकते हैं जो विमान या रेल द्वारा न जुड़े हों, बशर्ते वह दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो परन्तु जब दो स्थानों के बीच की दूरी का अधिकांश भाग विमान या रेल द्वारा तय किया जा सके तो केवल शेष दूरी सामान्यतः कार द्वारा तय किया जाना चाहिए।

विनियम 42 में संशोधन—स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि :

42 (2) (1) :

दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से स्थानान्तरण पर जाने वाले अधिकारी को अपना सामान

मालगाड़ी द्वारा ले जाने पर, खर्च की प्रतिपूर्ति निम्न-निम्न सीमाओं तक की जायेगी :—

वेतन सीमा	जहाँ उसका परिवार हो	जहाँ उसका परिवार न हो
(1)	(2)	(3)
2100 रुपए प्रतिमाह से	3000 किलो ग्राम	1000 किलो ग्राम
3060 रुपए प्रतिमाह	पूरा वेतन	2000 किलो ग्राम
3061 रुपए प्रतिमाह और अधिक		

विनियम 45 में संशोधन भविष्य-निधि :

45(2) : भविष्य निधि के समय-समय पर नियामक नियमों के अनुसार, बैंक भविष्य निधि में अपना योगदान देगा परन्तु उसके द्वारा दिए गए अंशदान की राशि, उक्त अधिकारी के, दिनांक 1-11-1987 को और इस तारीख से 31-12-1988 तक वेतन के 80 प्रतिशत के 10 प्रतिशत, दिनांक 1-1-1989 को और इस तारीख से 31-12-1989 तक वेतन के 90 प्रतिशत के 10 प्रतिशत और दिनांक 1-1-1990 को और इस तारीख से वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

विनियम 46 में संशोधन —उपदान :

46 (2) : किसी अधिकारी को देय उपदान की राशि पूरे किए गए प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए एक माह का वेतन होगी और वह 15 माह के वेतन से अधिक नहीं होगी। परन्तु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली हो तो वह 30 साल के बाद पूरे किए गए सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह के वेतन की आधी दर पर उपदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि पावे का पात्र होगा।

टिप्पणी:—यदि सेवा के पूर्ण वर्षों के बाद, खण्डित सेवा अवधि 6 माह या अधिक है तो उस अवधि के लिए उपदान समानुपातिक रूप से प्रदान किया जायेगा।

सुरेन्द्र मोहन , उप महाप्रबन्धक
(कार्मिक)

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1990

No. 3910.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980),

the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby make the following Regulations further to amend the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982.

2. Short title and commencement.—These Regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Amendment Regulations, 1990.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment to Regulation 3—Definitions

3(i) : "Pay" means basic pay including stagnation increment.

3(m) : "Salary" means the aggregate of the pay and dearness allowance.

Amendment to Regulation 4—Grades and Scales of Pay

4(1) : On and from 1-2-1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :—

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs. 4100—125—4600

Scale VI Rs. 3850—125—4350

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 3575—110—3685—115—3800

Scale IV Rs. 2925—105—3450

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 2650—100—3250

Scale II Rs. 1825—100—2925

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 1175—60—1475—70—1895—EB—95—2275—100—2675

On and from 1-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs. 6400—150—7000

Scale VI Rs. 5950—150—6550

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 5350—150—5950

Scale IV Rs. 4520—130—4910—140—5050—150—5350

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 4020—120—4260—130—4910

Scale II Rs. 3060—120—4260—130—4390

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 2100—120—4020

Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government.

Amendment to Regulation 5—Increments

5(1) : On and from 1-11-1987, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4(1) shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.
- (b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.
- (c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scale II, and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 130 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 140 for officers in the last stage of Scale III.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

5(2) : On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIB Examination as under :—

Those who have passed only part I of CAIB	Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both parts of CAIB	(i) Rs. 100/- p.m. after 1 year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits. (ii) Rs. 250/- p.m. after 3 years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

Note : If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher Scale, he shall be granted, on fitment into such higher Scale, additional increment(s) for passing CAIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

Amendment to Regulation 21—Dearness Allowance

On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

- (i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.
- (ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—
 - (i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 1650/- plus,
 - (ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 1650/- to Rs. 2835/- plus,
 - (iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 2835/- to Rs. 4020/- plus,
 - (iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4020/-.

Amendment to Regulation 22—House Rent Allowance

22(1) : On and from 1-11-1987, where an officer is provided with residential accommodation by the bank, 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

22(2) : On and from 1-11-1987, where an officer is not provided with any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'.	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/-
(ii) Other places in Area and Project Area Centres in Group 'B'.	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/-
(iii) Area II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	16% of the pay subject to a maximum of Rs. 250/-
(iv) Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 225/-

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the

first stage of the scale of pay in which he is placed, with a maximum of 160% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise.

22(3) : Where an officer resides in his own accommodation, he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below :—

A

The aggregate of :

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- (ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation :

(1) For the purpose of this Regulation "standard rent" means :—

- (a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;
- (b) Where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank.

Amendment to Regulation 23—City Compensatory Allowance

23(i) : On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place, provided that the city compensatory allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmugao, where it was not payable on 1-11-1987 shall be payable with effect from 20-8-1988.

Places	Rates
1	2
(a) Places in Area 1 and 1 in the State of Goa	6-1/4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	4% of basic pay subject to maximum of Rs. 135/- per month.

23(v) : Deputation Allowance :

On and from 1-11-1987, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay maximum Rs. 700/- and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay, maximum Rs. 350/-.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay maximum Rs. 350/-.

23(vi) : Officiating Allowance :

On and from 1-11-1987, if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

23(vii) : Closing Allowance :

On and from financial year 1989-90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150/- for each of the two closings.

23(x) : Hill and Fuel Allowance :

On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

Place	Rate
1	2
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	5% of pay subject to a maximum of Rs. 130/-
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	6-1/4% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-

Note : (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1-11-1987 and 30-4-1989 shall not be recovered. From 1st May 1989, onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.

Amendment to Regulation 24—Medical Aid & Hospitalisation Expenses :

24(1) : An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses :

On and from 1-11-1987 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/p.m.	Rs. 600/-
Rs. 3061/- p.m. and above	Rs. 800/-

Note An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation :

“FAMILY” of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 90 per cent in the case of an officer and 60 per cent in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.

981 GI/90—2

(v) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90 per cent in the case of an officer and 60 per cent in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diphtheria, Leprosy, Kidney Ailment.

Amendment to Regulation 25—Residential Accommodation :

On and from 1-11-1987, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6 per cent of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a further sum equal to 1½% of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

Amendment to Regulation 34—Sick Leave :

34(1) : On and from 1-1-1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost.

Amendment to Regulation 35—Additional Sick Leave :

On and from 1-1-1989, where an officer has put in a service of 24 years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

Amendment to Regulation 41—Mode of travel and expenses on travel :

On and from 1-4-1990 the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—

- (i) An officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
- (ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kms. He may, however,

travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

- (iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by air (economy class).
- (iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. However, when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

Amendment to Regulation 42—Transfer Travelling Allowance, etc. :

42(2)(i) : On and from 1-11-1987, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 2100/- p.m. to Rs. 3060/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 3061/- p.m. and above	Full Wagon	2000 kgs.

Amendment to Regulation 45—Provident Fund

45(2) : The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund, from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10 per cent of 80 per cent of pay on and from 1-11-1987 to 31-12-1988, 10 per cent of 90 per cent of pay on and from 1-11-1989 to 31-12-1989 and 10 per cent of pay on and from 1-1-1990, of the officer.

Amendment to Regulation 46—Gratuity :

46(2) : The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one-half of a months' pay for each completed year of service beyond thirty years.

Note : If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

SURINDER MOHAN, Dy. General Manager
(Per.)